

विकासशील देशों के सामने एआई संप्रभुता की चुनौती

अतनु बिरवासे

माइक्रोसॉफ्ट का अनुबंध

यूईई और अन्य देशों के साथ

है। अमेजन वेब सर्विसेज्

‘एडब्ल्यूएस यूरोपियन

सॉर्वेरेन क्लाउड’ प्रदान करता

है। निजी व्यवसाय भी

माइक्रोसॉफ्ट के एप्सूर और

गूगल क्लाउड से सॉर्वेरेन

क्लाउड का उपयोग कर

सकते हैं, जिसमें डेटा

स्थानीयकरण और

एन्क्रिप्शन शामिल है।

हालाकि, ऐसी ‘संप्रभुता को

सेवा के रूप में’ प्रस्तुत करने

को औपनिवेशिक राज का

एक समकालीन संस्करण

बताने वाली बयानबाजी भी

शुरू हो गई।

किसी भी स्थिति में, एआई संप्रभुता आज कई मध्यम-आय वर्ग के देशों के लिए एक दुखती रंग साबित हो रही है। उन्हें वित्तीय निवेश करने की अपनी क्षमता का आकलन, अपेक्षित आर्थिक लाभ, डेटा गोपनीयता और राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बुद्धिमानी भरे निर्णय लेने होंगे। अब जबकि हमारा देश ‘भारत एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन 2026’ आयोजित करने की तैयारी कर रहा है, यह ध्यान रखना जरूरी है कि फरवरी माह में पेरिस में हुए एआई क्रियान्वयन शिखर सम्मेलन 2025 में एआई संप्रभुता एक केंद्रीय मुद्दा था। महत्वपूर्ण बात यह है कि आज दुनियाभर में एआई से संबंधित बड़े पैमाने पर निवेश की दिशा-दशा एआई संप्रभुता की अवधारणा निर्धारित करती है। डिजिटल युग के आरंभिक और सबसे प्रभावशाली सिद्धांतकारों में से एक, फ्रांसीसी दार्शनिक बर्नार्ड स्टीगलर के अनुसार, तकनीक की पारंपरिक अवधारणा से आगे बढ़ने में दुनिया को अच्छी तरह समझना जरूरी है। उनका मानना था कि ‘मनो-राजनीति’ (साइकलोलॉजिटिक्स), जो, मीडिया और तकनीक हमारे मानस और ध्यान को आकार देने की क्षमता रखती है, 21वीं सदी को परिभाषित करती है। स्टीगलर का तर्क था कि तकनीक एक ‘फार्माकॉन’ है- जहर जो इलाज भी करता है – और यह हमें चुनना होगा कि हम तकनीक को अपना ‘इस्तेमाल’ करने दें या आधुनिक एजेंसियों से अपनी तर्कसंगत संप्रभुता वापस पाने के लिए इसका उपयोग ‘महत्वपूर्ण गहनता’ के लिए सावधानी से करें। हालांकि, 21वीं सदी की शुरुआत में ‘तकनीकी संप्रभुता’ की अवधारणा का पुनर्विन्यास हुआ था, जो मुख्यतः भू-राजनीतिक टकरावों और प्रतिस्पर्धा के परिणामवश था। वर्ष 2000 और 2010 के दशक की शुरुआत में, इंटरनेट संप्रभुता पर सबसे पहले चर्चा संभवतः चीन में हुई थी। फिर, इस एआई युग में विदेशी शक्तियों पर निर्भरता से बचने के लिए, विभिन्न देशों ने डिजिटल बुनियादी ढांचा, डेटा और एआई पर नियंत्रण स्थापित किया। साथ ही, ट्रम्प के पिछले कार्यकाल में 2018 में अमेरिका और चीन के बीच चले व्यापार युद्ध ने संप्रभु एआई होने की जरूरत को बढ़ावा दिया। एआई संप्रभुता किसी राष्ट्र या कंपनी द्वारा अपनी एआई तकनीकों को स्वतंत्र रूप से नियंत्रित करने की क्षमता है, जिसमें डाटा, बुनियादी ढांचा और स्वरूप शामिल हैं, ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा, नियामक अनुपालन और रणनीतिक स्वायत्तता सुनिश्चित हो सके। इसमें विदेशी नियंत्रण केंद्रों पर निर्भरता से बचना, संवेदनशील डाटा को अपने अधिकार क्षेत्र में बनाए

रखना और घरेलू ढांचे के भीतर एआई प्रणालियों का विकास एवं कार्यान्वयन शामिल है। सरल शब्दों में, संप्रभु एआई यह सुनिश्चित करना चाहता है कि एआई का उत्पादन घरेलू स्तर पर हो, जिसमें वह डेटा भी शामिल हो जिसका उपयोग एआई प्रशिक्षण में, अनुसंधान करते वक्त खोज करने में और किसी प्रश्न के उत्तर में आउटपुट के रूप में उत्पन्न करने वाला डाटा हो। इस प्रकार, ‘डेटा संप्रभुता’ और ‘एआई संप्रभुता’ आपस में जुड़ी हुई हैं, फिर भी अलग हैं। लेकिन संप्रभु एआई यह सुनिश्चित करता है कि एआई उनके सांस्कृतिक, नैतिक और कानूनी मानकों के अनुरूप हो। आज राष्ट्रों को जेनएआई के जोखिमों, फायदों और राष्ट्रीय सुरक्षा एवं आर्थिक विकास पर उनके संभावित प्रभाव के बारे में मालूम है। उदाहरण के लिए, 2035 तक, एआई भारत की अर्थव्यवस्था को 1.7 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ाने में मदद कर सकता है। अप्रैल 2024 में प्रकाशित विश्व आर्थिक मंच के एक लेख में, जिसका शीर्षक है ‘संप्रभु एआई- यह क्या है, और इसकी प्राप्ति के छह रणनीतिक स्तंभ’, के अनुसार, संप्रभु एआई के लिए प्रयास का अर्थ अनिवार्य रूप से डिजिटल अलगाव नहीं है, बल्कि रणनीतिक लचीलेपन के लिए प्रयास है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ मिलकर किया जा सकता है। रणनीतिक स्तंभ, जिनमें डिजिटल बुनियादी ढांचा, कार्यबल विकास, अनुसंधान, विकास एवं नवाचार, नियामक एवं नैतिक तानाबाना, एआई उद्योग को प्रोत्साहित करना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शामिल हैं, ये अव्यव देशों को अपनी संप्रभु एआई क्षमताओं को बढ़ाने में मदद करेंगे। इसलिए, संप्रभु एआई का मार्ग जटिल है और इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर सावधानीपूर्वक, दीर्घकालिक रणनीतिक योजना की आवश्यकता पड़ेगी। विभिन्न देशों में संप्रभु एआई के उदाहरणों में, सिंगापुर में एक सरकारी-वित्त पोषित एआई मॉडल मौजूद है, जो ग्यारह विभिन्न भाषाओं में संवाद करने में सक्षम है; मलेशिया का आईएलएफ्यूवेट मॉडल, जिसे एक स्थानीय निर्माण कंपनी ने बनाया है; और स्विट्जरलैंड में ‘एप्टैस’, तो दक्षिण कोरिया ने कोरियाई भाषा और डाटा आधारित ‘संप्रभु एआई’ के निर्माण के लिए 735 बिलियन डॉलर खर्च करने का इरादा किया है। भारत में, मार्च 2024 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया एआई मिशन को मंजूरी दी, जिसके तहत ‘भारत में एआई का निर्माण और भारत के लिए एआई को उपयोगी बनाने’ के उद्देश्य से 38,000 जीपीयू तैनात करके पांच वर्षों में 10,300 करोड़ से अधिक आवंटित किए जाने हैं। एनवीडिया के सीईओ जेन्सेन हुआंग ने 2024 की शुरुआत में घोषणा की थी कि ‘हर देश को संप्रभु एआई की आवश्यकता

है’। एआई संप्रभुता की वैश्विक दौड़ के बीच गौर करने लायक है कि संप्रभु एआई सेवाएं मुख्यतः अमेरिकी और चीन को चंद बड़ी तकनीकी विशेषज्ञता वाली कंपनियों द्वारा प्रदान की जा रही हैं। दुनिया के देश अवसर बुनियादी ढांचे और चिप्स के लिए अधिकांशतः उन पर दीर्घकालिक निर्भरता के लिए मजबूर हैं। ये बड़ी तकनीकी कंपनियां संप्रभुता को एक सेवा के रूप में प्रदान करके, संप्रभु प्रौद्योगिकी से जुड़े विमर्श को प्रभावित कर रही हैं। एनवीडिया ने इस विश्वव्यापी बुनियादी ढांचे को बनाने वाले हिस्सों को ‘एआई फ्रैक्टरी’ का नाम दिया है। और यह दुनिया भर के देशों में चिप्स और हार्डवेयर बुनियादी ढांचा स्थापित कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट का अनुबंध यूईई और अन्य देशों के साथ है। अमेजन वेब सर्विसेज् ‘एडब्ल्यूएस यूरोपियन सॉर्वेरेन क्लाउड’ प्रदान करता है। निजी व्यवसाय भी माइक्रोसॉफ्ट के एप्सूर और गूगल क्लाउड से सॉर्वेरेन क्लाउड का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें डेटा स्थानीयकरण और एन्क्रिप्शन शामिल है। हालांकि, ऐसी ‘संप्रभुता को सेवा के रूप में’ प्रस्तुत करने को आपनिवेशिक राज का एक समकालीन संस्करण बताने वाली बयानबाजी भी शुरू हो गई। उदाहरण के लिए, जून, 2025 में लंदन रियल्टी ऑफ बुद्धि में प्रकाशित लालेश खलीली के ‘सामूहिक संपत्ति, निजी नियंत्रण’ शीर्षक वाले लेख में इसका वर्णन किया गया है। पुराने समय में, 19वीं शताब्दी में यूरोपीय शक्तियों द्वारा आपनिवेशिक विस्तार के साधन के रूप में बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर (बीओटी) योजनाओं का उपयोग किया जाता था। जिसके तहत निजी,महानगरीय कंपनियां सड़क, रेलमार्ग, बंदरगाह, नहर, टेलीग्राफ लाइन आदि जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए जरूरत का धन, विशेषज्ञता और संसाधन प्रदान करती थीं। उपनिवेशों या उन जगहों पर जहां उनकी सरकार अपनी शक्ति और प्रभाव बढ़ाने का प्रयास कर

रही हो। हालांकि, यह एआई संप्रभुता के वर्तमान परिदृश्य से कितना मिलता-जुलता है और कहाँ पर भिन्न हैं, यह पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एवं नई राजनीतिक अर्थव्यवस्था के घटकों पर निर्भर है। बहरहाल, अब हर जगह की सरकारें किसी न किसी तरह से अपनी खुद की ‘संप्रभु’ एआई तकनीक बनाने पर अरबों खर्च करने के लिए मजबूर हैं। इसके कुछ प्रस्तावित विकल्प भी हैं। उदाहरण के लिए, अमेरिका और चीन की दिग्गज कंपनियों के लिए एक प्रतिस्पर्धी प्रतिद्वंद्वी विकसित करने के लिए, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के रैनेट स्कूल फॉर पब्लिक पॉलिसी के शोधकर्ताओं ने एक सार्वजनिक एआई कंपनी बनाने का सुझाव दिया है, जिस पर आने वाला खर्च मध्यम-आय वाले देशों के समूह मिलजुल कर उठाएँ।

किसी भी स्थिति में, एआई संप्रभुता आज कई मध्यम-आय वर्ग के देशों के लिए एक दुखती रंग साबित हो रही है। उन्हें वित्तीय निवेश करने की अपनी क्षमता का आकलन, अपेक्षित आर्थिक लाभ, डेटा गोपनीयता और राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बुद्धिमानी भरे निर्णय लेने होंगे।

लेखक भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता में सांख्यिकी के प्रोफेसर हैं।



मित्र नहीं हो सकता चीन भारत को सावधान रहना होगा

(लेखक- मनोज कुमार अग्रवाल)

अमेरिका के साथ व्यापार रिश्तों में कड़वाहट के बाद भारत का झुकाव चीन की ओर बढ़ा है लेकिन चीन चीन एक बार फिर अपनी विस्तारवादी नीति, उन्कावे की भाषा और ऐतिहासिक तथ्यों की मनमानी व्याख्या के सहारे भारत की संप्रभुता को चुनौती देने की कोशिश कर रहा है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने की संभावना बढ़ गयी है। शंघाई एयरपोर्ट पर भारतीय मूल की महिला पैमा यांगजोम घोंगडोक के साथ हुए व्यवहार पर भारत द्वारा दर्ज किए गए कड़े विरोध के बाद चीन की जो प्रतिक्रिया आई, वह न केवल अस्वीकार्य है. बल्कि अंतरराष्ट्रीय मर्यादाओं का भी खुला उल्लंघन करती है। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग का यह कहना है कि अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है, एक बार फिर यह साचित्त करता है कि बीजिंग ने तथ्यों, अंतरराष्ट्रीय कानूनों और कूटनीतिक शालीनता से ऊपर अपनी साम्राज्यवादी सोच को रखा है। भारत को आपत्ति बिन्दुक्त वैध है, क्योंकि किसी भारतीय नागरिक को सिर्फ इसलिए इनवैलिड पासपोर्ट का हवाला देकर रोका जाए कि उसका जन्मस्थान अरुणाचल प्रदेश है, यह चीन की मानसिकता को उजागर करने के लिए काफी है। पूरे मामले की शुरुआत पैमा वांगजोम के उस लोशन मीडिया पोस्ट से हुई, जिसमें उन्होंने बताया कि 21 नवंबर को लंदन से जापान जाते समय शंघाई एयरपोर्ट पर चीनी इमिग्रेशन ने उनके पासपोर्ट को इनवैलिड बताकर रोका। केवल इसलिए कि जन्मस्थान की कॉलम में अरुणाचल प्रदेश, भारत लिखा था। यह घटना कोई तकनीकी त्रुटि नहीं, बल्कि चीन की लंबे समय से अपनाई गई रणनीति, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अरुणाचल की भारतीय पहचान को चुनौती देने का प्रयास का एक और उदाहरण है। भारत ने सही ढंग से चीन को इस कार्रवाई पर कड़ा विरोध दर्ज कराया और इसे बेतुका, अवैध और उत्पीड़क बताया। लेकिन जवाब में चीन ने न केवल अपनी गलती मानने से इंकार किया, बल्कि उल्टे अरुणाचल पर अपना दावा दोहराकर भारत को उकसाने की कोशिश की। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और यह बात

ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और संवैधानिक रूप से निर्विवाद सत्य है। चीन द्वारा बार-बार उसके अस्तित्व को चुनौती देना केवल कूटनीतिक अशिष्टता नहीं, क्षेत्रीय अस्थिरता को भड़काने का प्रयास है। भारत का यह कहना बिन्दुक्त सही है कि एक यात्री को जन्मस्थान के आधार पर रोकना न सिर्फ बेतुका है बल्कि अंतरराष्ट्रीय विमानन व विजा मानदंडों के खिलाफ भी है। चीन का यह रवैया बताता है कि उसकी विस्तारवादी नीतियों अभी भी बरकरार हैं, चाहे वह दक्षिण चीन सागर हो, ताइवान हो या फिर अरुणाचल प्रदेश। बार-बार ये बयान और ऐसे उत्पीड़क कदम इस बात का संकेत हैं कि बीजिंग वास्तविकता स्वीकारने को तैयार नहीं है। लेकिन भारत के लिए यह आवश्यक है कि वह कड़े व स्पष्ट कूटनीतिक रुख के साथ दुनिया के सामने चीन की मनमानी व आक्रामकता को उजागर करता रहे। इस घटना ने एक बार फिर साबित किया है कि सीमा विवाद से परे भी चीन की नीति में भारत विरोध की गहरी जड़ें हैं। दुनिया इसे समझ रही है और भारत को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि वह अपने नागरिकों की सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों के प्रश्न पर किसी भी प्रकार का समझौता न करे। यह इसलिए भी जरूरी है कि क्योंकि चीन आए दिन अरुणाचल पर अपना दावा करता रहता है। दरअसल चीन अरुणाचल प्रदेश के 90,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अपना बताता है. वह इस क्षेत्र को चीनी भाषा में जांगनान कहता है और बार-बार दक्षिण तिब्बत का जिक्र करता है। चीन के नैप या मानचित्र में अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा दिखाया गया है। वो कभी-कभी इसका तथ्यांकित अरुणाचल प्रदेश के रूप में उल्लेख करता है। चीन के दक्षिण में अरुणाचल प्रदेश पर अपने एकतरफा दावे को पुष्ट करने का प्रयास करता रहता है। सिर्फ इतना ही नहीं, अरुणाचल प्रदेश के स्थानों को चीनी नाम देना देता रहा है। इसी साल मई महीने में अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों के नाम बदलने का बेतुका काम किया था। विस्तारवादी चीन ने अरुणाचल में 27 जगहों के नाम बदले थे। चीन ने ये नाम चीनी यानी मंडैरिन भाषा में रखे थे। चीन ने इन जगहों की सूची ग्लोबल टाइम्स अखबार की वेबसाइट पर जारी की थी। चीन ने बीते आठ सालों में

अरुणाचल प्रदेश की 90 से ज्यादा जगहों के नाम बदलें हैं। चीन द्वारा अरुणाचल के नाम बदलने पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी कहा था कि चीन का ये एक व्यर्थ और निरर्थक प्रयास है। अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। दरअसल पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में मैकमोहन लाइन की कानूनी स्थिति को लेकर विवाद है। यह तिब्बत और ब्रिटिश भारत के बीच की सीमा है, जिस पर 1914 के शिमला सम्मेलन में सहमति बनी थी, जिसे आधिकारिक तौर पर ग्रेट ब्रिटेन, चीन और तिब्बत के बीच सम्मेलन कहा जाता है। शिमला सम्मेलन में चीन का प्रतिनिधित्व चीन गणराज्य के एक महादूत द्वारा किया गया था। उसे 1912 में किंग राजवंश के पतन के बाद महादूत घोषित किया गया था। वर्तमान साम्यवादी सरकार 1949 में ही सत्ता में आई थी। चीनी प्रतिनिधि ने शिमला कन्वेंशन पर सहमति नहीं जताते हुए कहा कि तिब्बत को अंतरराष्ट्रीय समझौता करने का कोई अधिकार नहीं है। शिमला में मुख्य ब्रिटिश वार्ताकार हेनरी मैकमोहन थे। उन्हीं के नाम पर मैकमोहन लाइन का नाम रखा गया। यह लाइन भूटान की पूर्वी सीमा से चीन-म्यांमार सीमा पर इसु रजी दर्रे तक खींची गई थी। चीन मैकमोहन लाइन के दक्षिण में अरुणाचल प्रदेश में स्थित क्षेत्र पर अपना दावा करता है। अपने दावों का आधार तवांग और ल्हासा के मठों के बीच ऐतिहासिक संबंधों को भी मानता है। चीन इसे एक तरह की दबाव की रणनीति के रूप में देखता है। यह बीजिंग की प्रोपेगंडा वाली विचारधारा का हिस्सा है, जिसके तहत जब भी कोई भारत का कोई सेलेब्रिटी अरुणाचल प्रदेश का दौरा करता है, तो वह नाराजगी भरे बयान जारी करता है। हालांकि अरुणाचल प्रदेश के साथ भारत की संप्रभुता की मान्यता पूरी दुनिया में स्थापित है। अंतरराष्ट्रीय मानचित्रों में भी अरुणाचल प्रदेश भारत के हिस्से के तौर पर देखा जाता है। विदेशी मीडिया में भी इस बात को लेकर कभी किसी तरह की कोई कंप्यूजन नहीं रही, लेकिन चीन तिब्बत के साथ-साथ अरुणाचल प्रदेश पर भी दावा करने की कोशिश करता रहा है। दूसरी तरफ भारत ने हमेशा शांतिपूर्ण कूटनीति और अंतरराष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करते हुए सीमा विवादों के समाधान की कोशिश की है।

धन का भार

पाटलिपुत्र में नाभिकुमार की गिनती सबसे संपन्न लोगों में होती थी। लेकिन अपार धन-संपत्ति होते हुए भी उन्होंने कभी दान नहीं दिया था। कई लोगों ने उन्हें इस बारे में कहा था पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। एक रात उनके घर चोर ने संध लगाई। उसने सावधानी से घर का कीमती सामान एकत्र किया और उसकी एक बड़ी पोटली बनाई। पोटली सिर पर रखते ही वह गिर गई और आवाज होते ही नाभिकुमार की आंखें खुल गईं।

वह चोर के पास आए और पोटली उठाने में उसकी मदद करने लगे। चोर को डर से कांपते हुए देखकर नाभिकुमार ने उससे कहा-डरो मत,

तुम यह सब ले जा सकते हो। मगर तुम भी मेरे ही जैसे लगते हो। मैंने भी अपने जमा धन से किसी और के लिए कुछ नहीं निकाला। इसलिए मेरा धन भी मुझ पर भार की तरह है। अगर तुम भी मेरी तरह नहीं करते और पोटली में से थोड़ा सामान निकाल लिए होते तो तुम्हारे लिए इसे उठाना आसान हो जाता। खैर, तुम अब यह सामान ले जा सकते हो। चोर यह सुनकर दंग रह गया।

उसने प्रायश्चित्त करने के उद्देश्य से कहा-आप यह सब वापस ले लीजिए और मुझे क्षमा कीजिए। नाभिकुमार ने कहा- तुम्हें एक ही शर्त पर क्षमा किया जा सकता है। तुम इसमें से कुछ



धन ले लो और कोई काम-धंधा शुरू कर दो। इस प्रकार मेरा धन परोपकार के काम में लग जाएगा और तुम्हारा जीवन भी सुधर जाएगा। चोर ने वैसा ही किया। नाभिकुमार उस दिन से हर किसी की सहायता करने लगे।

विचारमंथन

(लेखक- सनत जैन)

- अस्थिर मुद्राओं की सूची में शामिल होगी भारतीय मुद्रा

भारत की अर्थव्यवस्था पिछले एक दशक में दुनिया की तेजी से उभरती हुई शक्तियों में शामिल रही है। हाल ही में जिस तरह से अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान (आईएफएम) ने भारत की मुद्रा स्थिति को लेकर कड़ी चेतावनी जारी की है, वह भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक चिंताजनक संकेत हैं। आईएफएम ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है, भारतीय रुपया जल्द ही अस्थिर मुद्राओं की सूची में शामिल किया जा सकता है। यह स्थिति भारत की अर्थव्यवस्था और अर्थ प्रबंधन पर घंभीर सवाल उठाता है। भारत सरकार के आर्थिक नीति-निर्माताओं के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई है। रुपये की कमजोरी कोई नई बात नहीं है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में इसकी गिरावट लगातार तेज हो रही है।

वैश्विक बाजार में डॉलर की मजबूती, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और विदेशी निवेश का भारत से पलायन यह तीनों ऐसे कारण हैं जो रुपये पर भारी दबाव डाल रहे हैं। बाहरी कारणों के साथ-साथ घरेलू बाजारों में भी चुनौतियाँ लगातार बढ़ रही हैं। बढ़ती महंगाई, नौकरी में छटनी और नई नौकरी नहीं मिलना, रोजगार के अवसरों में ठहराव, औद्योगिक उत्पादन में कमी से आर्थिक असंतुलन बुरी तरह से गड़बड़ाता जा रहा है। आईएफएम की चेतावनी का सबसे अहम कारण जिस तरह से डॉलर की खरीद और बिक्री करके रिजर्व बैंक और अन्य कारोबारी, रुपए की स्थिति को संभालने का प्रयास कर रहे हैं, आईएफएम ने इसको सबसे ज्यादा चिंताजनक माना है। यदि आईएफएम ने रुपया को अस्थिर मुद्रा की श्रेणी में डाल दिया, तो इसका सीधा असर आम भारतीय और भारतीय अर्थ व्यवस्था पर बढ़ा गहरा असर पड़ेगा। आयात महंगा होगा, पेट्रोल-डीजल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक सामान तक की कीमतें उसी हिसाब से बढ़ेंगी। महंगाई

तेजी के साथ बढ़ेगी। सरकार, कारोबारी और आम जनता के सामने आर्थिक मुश्किलें और भी बढ़ेंगी। यह स्थिति निवेशकों के विश्वास को शेयर बाजार से हटा सकती है, जिससे शेयर बाजार और विदेशी निवेश पर बड़ा नकारात्मक असर पड़ना तय है।

इस स्थिति के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक की बनती है। रिजर्व बैंक और आर्थिक नीतियों पर सरकार की दखलंदाजी 2019 के बाद से लगातार बढ़ती जा रही है। रिजर्व बैंक में अब अर्थशास्त्रियों का स्थान प्रशासनिक अधिकारियों और

सरकार के उन लोगों ने ले लिया है जो अर्थ का अ, ब, स, द भी नहीं जानते हैं। वर्तमान स्थिति में केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक को तत्काल ठोस कदम उठाने होंगे। विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करना होगा, सरकार को वित्तीय घाटे को नियंत्रित करना होगा। उद्योग एवं निर्यात से जुड़े क्षेत्रों को राहत पैकेज देना होगा। गैर जरूरी आयात और भारत से विदेशी मुद्रा को विदेश जाने से रोकने के लिए पर्यटन और घूमने-फिरने जैसे उपायों पर रोक लगानी होगी। ऐसे उपाय करने होंगे, जो रुपये को स्थिर करने में मदद कर सकते हों। सरकार और रिजर्व बैंक को महंगाई पर नियंत्रण रखने की नीतियां बनानी होंगी। नीति-निर्माण में पारदर्शिता के साथ काम करना होगा। भारत के पास संभावनाएँ बहुत हैं। इसके लिए सरकार को स्वयं अर्थव्यवस्था के सत्य को समझने की जरूरत है। सरकार की जिम्मेदारी है कि वह अर्थव्यवस्था को लेकर आम आदमी को भी सही स्थितियां बताए। आर्थिक प्रबंधन के मोर्चे पर जो स्थिति

देखने को मिल रही है, यदि इसे समय रहते संभाला नहीं गया, तो यह चूक देश को भारी महँगी पड़ सकती है। आईएफएम की चेतावनी को एक तकनीकी रिपोर्ट मानकर अनदेखा करना इस समय की सबसे बड़ी भूल होगी। अर्थव्यवस्था के बारे में भारत के लिए यह एक स्पष्ट संकेत है। भारतीय अर्थव्यवस्था को त्वरित और निर्णायक सुधारों की जरूरत है। सही समय पर सही कदम न उठाए गए, तो रुपया केवल अस्थिर मुद्रा नहीं, बल्कि आर्थिक जोखिम का बड़ा कारण बन सकता है। भारत के आयात और निर्यात में असंतुलन बना हुआ है, जिसके कारण विदेशी मुद्रा कम आ रही है। आयात करने के लिए हमें ज्यादा विदेशी मुद्रा खर्च करना पड़ रही है। सारे उद्योग और व्यापार इस समय वैश्विक कारोबार कर रहे हैं। इसका असर भारत के आम आदमी और भारतीय अर्थ व्यवस्था में पड़ना तय है।



लीला पैलेस ने दुबई के पाम में 25 फीसदी हिस्सेदारी खरीदी

नई दिल्ली लीला पैलेस, होटल्स एंड रिसॉर्ट्स ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली विदेशी सहायक कंपनी एरीज होल्डिंग्स के माध्यम से बोर्लॉन होल्डिंग्स के जरिए दुबई के पाम जुमेरा में लक्जरी होटल सॉफ़िटेल् द पाम एफ़जेड्स में 25 फीसदी हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया। कंपनी ने इस हिस्सेदारी के लिए 437 करोड़ रुपये का निवेश किया है। शेष 75 फीसदी हिस्सेदारी बुकफील्ड द्वारा प्रबंधित निजी फंड खरीदेगा। संपत्ति 23 एकड़ में फैली है और इसमें 546 कमरे हैं, जिनमें 361-कमरों वाला लक्जरी होटल, 182 ब्रांडेड आवास और तीन विशेष विला शामिल हैं। यह कदम लीला पैलेस के अंतरराष्ट्रीय विस्तार रणनीति का हिस्सा है, जिसे अक्टूबर में निदेशक मंडल ने मंजूरी दी थी।

एक्रस का 922 करोड़ का आईपीओ 3 दिसंबर से खुलेगा

नई दिल्ली एक्रस जो टिकाऊ उपभोक्ता उत्पादों और एयरोस्पेस कल-पुर्जों के अनुबंध पर विनिर्माण में विशेषज्ञता रखती है, ने अपने आरंभिक सार्वजनिक निगम (आईपीओ) के लिए प्राइस बैंड 118-124 रुपए प्रति शेयर तय किया है। कंपनी का आईपीओ कुल 922 करोड़ रुपए का है, जिसमें 670 करोड़ रुपए नए शेयर जारी करने से और 252 करोड़ रुपए की बिक्री पेशकश शामिल है। कुल ओएफएस में 2.03 करोड़ शेयर शामिल हैं। आईपीओ 3 दिसंबर से 5 दिसंबर तक निवेशकों के लिए खुला रहेगा। बड़े (एंकर) निवेशक 2 दिसंबर को बोली लगा सकते हैं। एक्रस अपने शेयरों को 12 दिसंबर को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कर सकती है। इस आईपीओ के जरिए कंपनी पूंजी जुटाकर अपने उत्पादन और विकास परियोजनाओं का विस्तार करने की योजना बना रही है।

सुदीप फार्मा के आईपीओ की शानदार लिस्टिंग

नई दिल्ली सुदीप फार्मा लिमिटेड का शेयर शुक्रवार को बाजार में 593 रुपए के निगम मूल्य के मुकाबले जोरदार प्रदर्शन करते हुए सूचीबद्ध हुआ। बीएसई पर शेयर 733.95 रुपए पर शुरू हुआ और बाद में 777 तक पहुँचकर 31 फीसदी की बढ़त दर्ज की। एनएसई पर यह 730 रुपए पर सूचीबद्ध हुआ। कंपनी का बाजार मूल्यांकन 8,567.72 करोड़ रुपए रहा। इसके आईपीओ को 93.71 गुना अभिमान मिला। सुदीप फार्मा दवाइयों, खाद्य और पोषण उत्पादों के लिए विशेष सामग्री और एक्सीपिएंट्स आधुनिक तकनीक से बनाती है।

रेनबो चिल्ड्रन्स हॉस्पिटल उतर भारत में करेगा बड़ा विस्तार

रेनबों की अगले तीन साल में 900 बेड जोड़ने की योजना
नई दिल्ली हैदराबाद स्थित रेनबो चिल्ड्रन्स हॉस्पिटल, जो बच्चों के इलाज और प्रसवकालीन देखभाल में विशेषज्ञ है, अब उत्तर भारत में अपनी पैठ मजबूत करने की तैयारी कर रहा है। समूह अगले तीन वर्षों में अपने अस्पताल नेटवर्क में लगभग 900 बेड जोड़ने की योजना बना रहा है, जिनमें से आधे यानी 450 बेड राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में होंगे। इन बेडों में एक 325-बेड वाला मुख्य अस्पताल और एक 125-बेड वाला सैटेलाइट अस्पताल शामिल होगा। रेनबो ने पहले से ही दक्षिण भारत के प्रमुख शहरों में अपनी पहचान बनाई है। अब समूह बेंगलूरु में इलेक्ट्रॉनिक सिटी में 90 बेड और हैनूर में 60 बेड, पुणे में 150 बेड और कोयंबतूर में 130 बेड जोड़ने का इरादा रखता है। पुणे की इकाई को एसेट-लाइट सैटेलाइट मॉडल के तहत विकसित किया जाएगा। समूह इस विस्तार पर कुल 800-900 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बना रहा है। योजना में ग्रीनफील्ड अस्पताल और एसेट-लाइट सैटेलाइट मॉडल का मिश्रण शामिल है। सैटेलाइट अस्पताल की लागत लगभग 70 लाख रुपये प्रति बेड होगी, जबकि एसेट-हैवी मॉडल की लागत इससे अधिक होगी।

रतन टाटा का सेशेल्स बीचफ्रंट विला बिकाऊ

85 लाख वाली प्रॉपर्टी के 55 करोड़ देने को तैयार है ग्राहक



नई दिल्ली सेशेल्स के माहे द्वीप पर स्थित रतन टाटा का खूबसूरत बीचफ्रंट विला एक बार फिर सुर्खियों में है। टाटा को यह संपत्ति इसलिए मिल सकी थी क्योंकि सेशेल्स सरकार

ने उन्हें विशेष अनुमति दी थी, जबकि देश में आमतौर पर विदेशी नागरिकों को प्रॉपर्टी खरीदने की अनुमति नहीं होती।

उस समय एयरसेल के संस्थापक सी. शिवशंकरन ने इस विला की खरीद में रतन टाटा की मदद की थी। अब जानकारी सामने आई है कि शिवशंकरन और उनका परिवार या सहयोगी

इस विला को खरीदने में गहरी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। विला की आधिकारिक वैल्यूएशन पेशेवर विशेषज्ञों द्वारा लगभग 85 लाख रुपये आंकी गई है, लेकिन संभावित खरीदार इसे करीब 6.2 मिलियन डॉलर (लगभग 55 करोड़ रुपये) में खरीदने की इच्छा जता रहे हैं। यदि यह सौदा पूरा होता है, तो बिक्री से प्राप्त राशि रतन टाटा एंडॉवमेंट फाउंडेशन और रतन टाटा एंडॉवमेंट ट्रस्ट के पास जाएगी। उल्लेखनीय है कि रतन टाटा ने अपनी वसीयत में

इस विला को अपनी निवेश फर्म आरएनटी एसोसिएट के नाम किया था, जो सिंगपुर में पंजीकृत है और भारत के कई उभरते स्टार्टअप्स में निवेश कर चुकी है। हालांकि, डील अभी फाइनल नहीं हुई है। जब शिवशंकरन से विला खरीदने की संभावित बातचीत के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं। यह बयान संकेत देता है कि बातचीत भले चल रही हो, पर अभी समझौता पक्का नहीं हुआ है।

बैजू रवींद्रन अमे रिकी अदालत में पेश करेंगे ग्लास ट्रस्ट के खिलाफ साक्ष्य

► अंतरराष्ट्रीय कानूनी विवाद में बायजू की चुनौती नई दिल्ली

एडोके कंपनी बायजू के संस्थापक बैजू रवींद्रन अमेरिका की अदालत में साक्ष्य प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उनका दावा है कि ग्लास ट्रस्ट और समाधान पेशेवरों ने उन्हें और अन्य संस्थापकों को बार-बार गुमराह किया और यह झूठा आरोप लगाया कि उन्होंने 53.3 करोड़ डॉलर (अल्फा

फंड्स) का गबन किया। यह साक्ष्य डेलावेयर दिवाला अदालत के 20 नवंबर, 2025 के आदेश के खिलाफ अपील के हिस्से के रूप में और संबंधित पक्षों के खिलाफ 2.5 अरब डॉलर से अधिक के दावे के तहत पेश किया जाएगा। रवींद्रन ने अपनी कंपनी थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड (टीएलपीएल) के लिए डेलावेयर दिवाला अदालत में अलग याचिका दायर की है। उनका कहना है कि अदालत ने हजाने का फेसला समय से पहले जारी किया

और ग्लास ट्रस्ट ने सुनवाई से पहले अपनी हजाने की मांग वापस ले ली थी। उनकी टीम का कहना है कि अदालत ने गलती से डिफॉल्ट फैसले में हजाने का पंचाट शामिल कर दिया, जबकि यह केवल दस्तावेज और जानकारी समय पर न देने के लिए दिया जाना चाहिए था। रवींद्रन ने मीडिया को बताया कि पिछले दो सालों से ग्लास ट्रस्ट उनकी और कंपनी की छवि खराब करने में लगा रहा है। उन्होंने कहा कि यह



धन टीएलपीएल और कंपनी के विस्तार के लिए इस्तेमाल किया गया। रवींद्रन ने स्पष्ट किया कि आने वाले समय में वह और अन्य संस्थापक भारतीय और अमेरिकी अदालतों में मुकदमा दायर करेंगे। रवींद्रन का कहना है कि साक्ष्य जल्द ही भारतीय अदालतों के साथ भी साझा किए जाएंगे।

स्टेनलेस स्टील उद्योग के लिए अलग नीति की मांग

स्टेनलेस स्टील को राष्ट्रीय इस्पात नीति में शामिल करने का प्रस्ताव

नई दिल्ली जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड (जेएसएल) के एक प्रमुख अधिकारी ने कहा है कि भारतीय स्टेनलेस स्टील उद्योग को केवल राष्ट्रीय इस्पात नीति में एक अध्याय जोड़ने की बजाय स्वतंत्र और प्रतिबद्ध नीति की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि स्टेनलेस स्टील का उत्पादन, कच्चा माल और अनुप्रयोग कार्बन स्टील से अलग होते हैं, इसलिए इसे अलग नीतिगत ढांचे की जरूरत है। जेएसएल भारत की सबसे बड़ी स्टेनलेस स्टील उत्पादक कंपनी है और विशेष स्टील के घरेलू बाजार में इसका लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा है। अधिकारी का कहना है कि केवल एक अध्याय जोड़ने से इस उद्योग का महत्व और मूल्य कम हो जाएगा। इस्पात मंत्रालय ने लंबे समय से चली आ रही चिंताओं को दूर करने के लिए स्टेनलेस स्टील को राष्ट्रीय इस्पात नीति में शामिल करने का प्रस्ताव रखा है। मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि नई नीति में स्टेनलेस स्टील पर एक अलग अध्याय होगा। उन्होंने कहा कि इस नीति में क्षेत्रवार वास्तविकताओं को ध्यान में रखा जाएगा, जैसे कम क्षमता का उपयोग, उच्च उत्पादन लागत और कच्चे माल की कमी। अधिकारी ने यह भी कहा कि स्टेनलेस स्टील के लिए मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना जरूरी है। इसमें नीति स्तर पर शिक्षा, जमीनी स्तर पर जागरूकता और प्रतिभा संपन्न श्रमशक्ति शामिल है। उन्होंने जोर दिया कि स्टेनलेस स्टील की वैल्यूड सामान्य स्टील से पूरी तरह अलग होती है, इसलिए प्रशिक्षित श्रमिक और तकनीकी तैयारी आवश्यक है।



भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला संपन्न, 18 लाख से अधिक दर्शक पहुंचे

राजधानी के भारत मंडपम में 14 दिनों तक चला भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला (आईआईटीएफ)

नई दिल्ली भारतीय व्यापार प्रदर्शनी संगठन (आईटीपीओ) के प्रबंध निदेशक नीरज खारवाल ने कहा कि 14-दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में विभिन्न क्षेत्रों की व्यापक भागीदारी रही और कुल 18 लाख से अधिक लोग मेला देखने आए। इस दौरान 18 लाख से अधिक आगतुक व्यापार मेला देखने आए। वाणिज्य मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि व्यापार मेला में भागीदार राज्य श्रेणी के तहत राजस्थान ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि बिहार ने रजत पदक और उत्तर प्रदेश ने कांस्य



पदक हासिल किया। विदेशी मंडप श्रेणी में थाईलैंड ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि ईरान और दुबई को क्रमशः रजत और कांस्य पदक मिला। मंत्रालयों और सरकारी विभागों की श्रेणी में रक्षा मंत्रालय को स्वर्ण पदक मिला। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और बैंक की श्रेणी में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। भारतीय व्यापार प्रदर्शनी

देश की पहली सात सीटों वाली इलेक्ट्रिक एसयूवी महिंद्रा एक्सईवी 9एस लॉन्च

इसका बेहतरीन डिजाइन व फीचर्स, 14 जनवरी 2026 से होगी बुकिंग शुरू

नई दिल्ली

भारत की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल महिंद्रा की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री होती है। निर्माता की ओर से देश की पहली सात सीटों वाली इलेक्ट्रिक एसयूवी महिंद्रा एक्सईवी 9एस लॉन्च कर दी है। इस एसयूवी में दमदार बैटरी और मोटर दी गई है। निर्माता की ओर से इसे बेहतरीन डिजाइन और फीचर्स के साथ लॉन्च किया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस एसयूवी में बेहतरीन फीचर्स दिए गए हैं। इसमें एडोप्टिव क्रूज कंट्रोल, ड्राइविंग के लिए कई मोड्स, बूरे ट मोड, एलईडी



डीआरएल, सीबे वेंशल टर्न इंवीकेटर, लेडर रैप इंटरियर, 18 इंच अलॉय व्हेल्स, पैनोरमिक सनरूफ, एलईडी हेडलाइट्स, एलईडी टेल लाइट, पावरड ड्राइवर सीट, फलश डोर हैंडल, ड्यूल जोन ऑटो एसी, की-लैस एंट्री, विंडशील्ड ड के लिए ऑटो डिफॉगर, ट्रिपल रे क्रोन, 16 से पीकर, हरमन ऑडियो सिस्टम, एनएफसी कार्ड, वायरलेस एंड्राइड ऑटो, एप्पल कारपेले, कनेक्टेड फीचर्स, अमेजन एलेक्सा, सात एयरबैग, लेवल-2 एडीएस, 360 डिग्री कैमरा, फंटे पार्किंग सेंसर, सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक, ड्राइवर डॉजिनेस सिस्टम, टीपीएमएस जैसे फीचर्स दिए गए हैं। महिंद्रा की ओर से इस एसयूवी को भी दिया गया है। जिसमें 59 और 79 की क्षमता की बैटरी लगी है। फास्ट चार्ज से एसयूवी को 20 मिनट में 20 से 80 फीसदी चार्ज किया जा सकता है। इसकी मोटर से इसे 180 किलोवाट की पावर मिलती है। साथ ही रीजनरेटिव तकनीक को भी दिया गया है। महिंद्रा की एक्सईवी 9एस को भारतीय बाजार में 19.95 लाख रुपए की एक्सेस शोल्डर प्राइज पर लॉन्च किया है। इसके टॉप वैरिएंट की एक्सेस शोल्डर कीमत 29.45 लाख रुपए है। निर्माता की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक एसयूवी की 14 जनवरी 2026 से बुकिंग शुरू हो जाएगी। इसके बाद एसयूवी की डिलीवरी को 23 जनवरी 2026 से की जाएगी।

वेपार

मीशो की आईपीओ के ज रिफ 5,421 करोड़ जुटाने की योजना



नई दिल्ली ई-कॉमर्स कंपनी मीशो, जो सॉफ्टबैंक समर्थित है, अपने प्रारंभिक सार्वजनिक निगम (आईपीओ) के जरिए 5,421 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखती है। कंपनी ने इसके लिए 105-111 रुपये प्रति शेयर का मूल्य दायरा तय किया है। आईपीओ के ऊपरी छोर पर मीशो का कुल मूल्यांकन लगभग 50,096 करोड़ रुपये (5.6 अरब डॉलर) होगा। बड़े निवेशक (एंकर) बोली 2 दिसंबर, आम निवेशकों के लिए बोली 3 से 5 दिसंबर को लगा सकेंगे। इसके आईपीओ की शेयर बाजार में लिस्टिंग 12 दिसंबर को होगी। इस आईपीओ में 4,250 करोड़ रुपये नए शेयर और 1,171 करोड़ रुपये ओएफएस (पुराने शेयरों की बिक्री) शामिल हैं। मीशो का यह कदम कंपनी को विस्तार के लिए नई पूंजी जुटाने और निवेशकों को तरलता प्रदान करने में मदद करेगा।

शेयर बाजार गिरावट पर बंद



ट्रेक महिंद्रा, बजाज फाइनेंस, टीसीएस, टाटा स्टील के शेयर उछले जबकि भारती एयरटेल, इन्फोसिस, एक्सिस बैंक, बीईएल, बजाज फिनसर्व, ट्रेड, एलएंडटी, एचडीएफसी बैंक, एचसीएल ट्रेक के शेयर गिरे। वहीं बाजार जानकारों के अनुसार दूसरी तिमाही के जीडीपी आंकड़े और आईआईपी डेटा आने से पहले बाजार में हल्की मुनाफावसूली रही। इससे पहले आज सुबह बाजार शुरुआती गिरावट से उबरकर हरे निशान में पहुंच गया। सेंसेक्स 85,821 अंक पर 101 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। वहीं एनएसई निफ्टी 50 35 अंकों की बढ़त के साथ 26,251 अंक पर पहुंच गया। वहीं एशिया-पैसिफिक बाजारों में मिश्रित रुझान देखने को मिला। अमेरिका में थैक्सनिंग की वजह से स्टॉक फ्यूचर्स सामान्य रहे। नेस्डेक कम्पोजिट अपनी सात महीने की बढ़त को रोकने की ओर दिखता। अमेरिका में डॉव जोंस इंडस्ट्रियल एवरेज फ्यूचर्स 10 अंक बढ़े, जबकि एसएंडपी 500 और नेस्डेक 100 फ्यूचर्स लगभग स्थिर रहे। नवंबर में अमेरिकी बाजार कमजोर रुझान के साथ बंद होने की संभावना है

एग्रेसिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड की परिसंपत्ति बढ़कर 2.5 लाख करोड़ पहुंची

अक्टूबर 2024 में प रिसंप ति 2.21 लाख करोड़ रुपए थी
नई दिल्ली निवेशकों के बीच एग्रेसिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (एएमएफआई) के अनुसार, अक्टूबर 2025 तक इस श्रेणी का परिसंपत्ति आधार (एयूएम) 2.5 लाख करोड़ रुपए हो गया, जो सालाना आधार पर 13 फीसदी की वृद्धि है। अक्टूबर 2024 में यह 2.21 लाख करोड़ रुपये था। निवेशक आधार भी मजबूत हुआ, और फोलियो की संख्या 56.41 लाख से बढ़कर 60.44 लाख हो गई। यह वृद्धि ऐसे समय में हुई जब निफ्टी ने एक साल के लिए गिरावट और उच्च अस्थिरता देखी। विशेषज्ञों के अनुसार, निवेशक ऐसे फंड की ओर आकर्षित हो रहे हैं जो इक्रिटी और डेट दोनों में निवेश कर विकास और स्थिरता का संतुलन प्रदान करें। एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स ने विभिन्न समय-सीमाओं में मजबूत रिटर्न दिया है। आईसीआईसीआई यूटिलिटी एंड डेब्ट फंड ने दो-वर्षीय सीएजीआर 19.6 फीसदी और पांच-वर्षीय सीएजीआर 24.7 फीसदी के साथ शीर्ष प्रदर्शन किया। इसके बाद में हिंदी मेलुलाइफ एग्रेसिव हाइब्रिड फंड ने क्रमशः 19.3 और 20.4 फीसदी का रिटर्न दिया। बंधन, एडलविश और इनवेस्को इंडिया के फंड्स ने भी दो अंकों का रिटर्न दर्ज किया है।

भारतीय दो पहिया बाजार में 125सीसी सेगमेंट में बढ़ी प्रतिस्पर्धा



नई दिल्ली भारतीय दोपहिया बाजार में 125सीसी स्कूटर सेगमेंट में टीवीएस, होंडा, हीरो, सुजुकी और यामाहा जैसे ब्रांडों ने कई मजबूत विकल्प लॉन्च किए हैं, जो युवाओं और शहरों में रोजाना सफर करने वालों के बीच खास लोकप्रिय हैं। इस सेगमेंट में टीवीएस एनएटॉक 125 को सबसे प्रभावशाली परफॉमेंस स्कूटर माना जाता है। इसका 124.8सीसी इंजन 7.5 केडब्ल्यू पावर और 11.5 एनएम टॉर्क देता है, जो इसे 98 किमी/घंटा की टॉप स्पीड तक पहुंचाता है। डिजिटल स्पीडोमीटर, राइडिंग मोड्स, एलईडी लाइटिंग और यूएसबी चार्जिंग जैसे फीचर्स इसे और भी आकर्षक बनाते हैं। होंडा डियो 125 भी इस वर्ग में एक मजबूत विकल्प है। इसका 125सीसी इंजन 6.11 केडब्ल्यू पावर और 10.5 एनएम टॉर्क पैदा करता है। रिमोट की, ब्ल्यूथूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन और टीएफटी मीटर जैसे एडवांस फीचर्स इसे मॉडर्न राइडर्स की पसंद बना रहे हैं। हीरो जूम 125 अपनी हल्की बोडी, स्पोर्टी डिजाइन और 7.3 केडब्ल्यू पावर वाले इंजन के साथ शहरी सड़कों के लिए खास तौर पर उपयुक्त है। इसकी 95 किमी/घंटा की टॉप स्पीड और सीटिंगशिफ्ट एलईडी विंक्स जैसे फीचर्स युवाओं को आकर्षित करते हैं। सुजुकी अवेनिस 125 अपने स्पोर्टी लुक और 21.5-लीटर स्टोरेज क्षमता की वजह से प्रैक्टिकल और स्टाइलिश दोनों का मिश्रण है। इसका 6.3 केडब्ल्यू पावर देने वाला इंजन आसानी से 90 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ लेता है। वहीं यामाहा रेझर 125 अपने टफ डिजाइन और 6.0 केडब्ल्यू पावर वाले इंजन के साथ 90 किमी/घंटा की स्पीड देती है। इसमें डिजिटल क्लस्टर, एलईडी हेडलाइट और ऑटोमैटिक स्टार्ट/स्टॉप सिस्टम शामिल हैं। 73,430 रुपये से शुरू होने वाली कीमत के साथ ये पांचों स्कूटर्स 125 सीसी सेगमेंट में पावर और फीचर्स के बेहतरीन विकल्प बनकर उभर रहे हैं।

रबी में लगायें गेहूं



जे.जी. 315
जवाहर 218 जे.जी. 130 जे.जी. 412
जे.जी. 16 जे.जी. 11 जे.जी. 74 1 आईसीसीव्ही.10 (विजय
भारती जे.जी. 1
जे.जी. के. 1

संक्षिप्त समाचार

पेरू के पूर्व राष्ट्रपति विजकारा को 14 साल की जेल

लीमा, एजेंसी। पेरू की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति मार्टिन विजकारा को एक दक्षिणी राज्य के गवर्नर के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार योजना में उनकी भूमिका के लिए 14 साल जेल की सजा सुनाई है। विजकारा को तत्काल कारावास की सजा सुनाई गई और सार्वजनिक पद से नौ वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया गया। अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि विजकारा ने मोकेगुआ के गवर्नर के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान दो प्रमुख परियोजनाओं – एक सिंचाई प्रणाली और एक अस्पताल के निर्माण – के लिए ठेके देने के बदले में कंपनियों से अवैध भुगतान प्राप्त किया था। अधिकारियों ने विजकारा पर निर्माण कंपनियों से लगभग 611,000 डॉलर की रिश्वत लेने का आरोप लगाया। अभियोजकों ने 15 वर्ष की जेल की सजा का अनुरोध किया था।

पाकिस्तान : खैबर पख्तूनख्वा में चेक पोस्ट पर आतंकवादी हमले में 3 पुलिसकर्मी मारे गए

इस्लामाबाद, एजेंसी। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बुधवार को एक जांच चौकी पर आतंकवादियों के हमले में तीन पुलिस कर्मियों की मौत हो गई। जिला पुलिस अधिकारी खान जैब ने बताया कि यह हमला हंगू जिले के काजी तालाब पुलिस चेकपोस्ट पर हुआ, जब आतंकवादियों ने पास के पहाड़ से सुरक्षाकर्मियों पर गोलीबारी की। पुलिस ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद भीषण गोलीबारी शुरू हो गई। हालांकि, गोलीबारी में तीन पुलिसकर्मी मारे गए। जैब ने बताया कि हमलावरों की तलाश के लिए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी ने हमले की कड़ी निंदा की और बिना किसी देरी के अतिरिक्त सुरक्षा बलों को घटनास्थल पर भेजने का आदेश दिया।

नेपाल : जेन-जी और यूएमएल कैडरों में झड़प, एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार हिंसा

धनगढ़ी, एजेंसी। नेपाल के धनगढ़ी शहर में बुधवार को जेन-जी समूह और केपी शर्मा ओली के शत्रुत्व वाली पार्टी सीपीएम-यूएमएल के कार्यकर्ताओं के बीच टकराव हो गया। एक सप्ताह के भीतर हिंसा की यह दूसरी घटना है। इस झड़प में प्रदर्शकारी एक जेन-जी को हल्की चोट आई है। यूएमएल नेता महेश बस्नेत के शहर में आने से पहले जेन-जी शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि तनाव तब बढ़ा, जब बाइक पर आए यूएमएल कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शनकारियों पर हमला कर दिया। बस्नेत नेशनल यूथ एसोसिएशन नेपाल के एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए धनगढ़ी जा रहे थे। कैलाली जिला पुलिस कार्यालय के अनुसार, पिछले सप्ताह बारा जिले में हुई हिंसा को देखते हुए पुलिस ने पहले ही सुरक्षा कड़ी कर दी थी। रविवार को कुछ जेन-जी ने बिराटनगर हवाई अड्डे के पास महेश बस्नेत की गाड़ी पर स्याही फेंक दी थी। इससे कुछ ही दिन पहले सिमरा चौक पर यूएमएल महासचिव शंकर पोखरेल और बस्नेत को रोकने की कोशिश कर रहे जेन-जी कार्यकर्ताओं और यूएमएल कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें छह युवा घायल हो गए थे। इस दौरान पथराव हुआ था। हवाई अड्डे पर तोड़फोड़ के कारण उड़ानों को कई घंटों के लिए रोकना पड़ा था।

इसाइल ने लौटाए 15 और फलस्तीनियों के शव, सीजफायर के दूसरे चरण पर चर्चा के लिए मिले तीन देशों के अधिकारी

तेल अवीव, एजेंसी। इस्राइल ने पंद्रह और फलस्तीनियों के शव सौंप दिए हैं। संघर्षविराम समझौते का पहला चरण खत्म होने के करीब है और अधिकारी दूसरे चरण पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए हैं। गाजा में अस्पताल के अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। यह घटनाक्रम उस समय हुआ है, जब फलस्तीनी लड़ाकों ने इस्राइली बंधक ड्रॉर और के अवशेष लौटाए हैं। इस्राइली सेना का कहना है कि हमास के सात अक्टूबर 2023 के हमले में उनकी मौत हो गई थी। समझौते के तहत इस्राइल हर एक बंधक के बदले 15 फलस्तीनी शव लौटाने के लिए तैयार हुआ है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, ताजा आदान-प्रदान के बाद इस्राइल अब तक कुल 345 फलस्तीनी शव गाजा वापस भेज चुका है। ये आदान-प्रदान पिछले महीने शुरू हुए थे। गाजा में अभी भी दो लोग हमास की कैद में हैं। इनमें एक इस्राइली और एक थाई नागरिक हैं। तुर्किये, कतर और मिस्र के अधिकारियों ने बुधवार को काहिरा में मुलाकात की, ताकि संघर्षविराम के दूसरे चरण पर बात की जा सके। दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे पर संघर्षविराम के उल्लंघन के आरोप लगाए जा रहे हैं। इसके बावजूद यह संघर्षविराम अब तक बना हुआ है। समझौते के अगले चरणों में एक अंतरराष्ट्रीय बल को तैनात करना और गाजा के लिए एक अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक ढांचा बनाना शामिल है, जो पुनर्निर्माण कार्य की निगरानी भी करेगा। सशस्त्र अंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण बल का काम सुरक्षा बनाए रखना और हमास का निरस्त्रीकरण सुनिश्चित करना होगा। यह इस्राइल की मुख्य मांग है।

व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी की रिश्तेदार हिरासत में, ब्राजील डिपोर्ट किया जा सकता है

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका की इमिग्रेशन एजेंसी आईसीई ने व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलीन लेविट के भतीजे की मां, ब्रूना कैरोलाइन फेरैरा को गिरफ्तार किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्हें जल्द ही ब्राजील वापस भेजा जा सकता है। यह मामला तब सामने आया जब आईसीई अधिकारियों ने उन्हें मैसाचुसेट्स से पकड़कर लुइसियाना की एक डिटेंशन सेंटर में भेज दिया। अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी का कहना है कि ब्रूना एक ट्रैफिक वीजा पर अमेरिका आई थीं, लेकिन उनका वीजा 1999 में खत्म हो गया था। उनका आरोप है कि ब्रूना ने वीजा की टाइम लिमिट पार कर दी और उन पर हमले के शक में कार्रवाई की गई है।

ब्रूना के वकील टॉड पोमरलीउन बातों से पूरी तरह सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि ब्रूना पर कोई अपराधिक मामला नहीं है। वे डीएसीए नाम के उस सरकारी प्रोग्राम के

तहत कानूनी तौर पर अमेरिका में रह रही थीं, जो बच्चों के तौर पर आए लोगों को सुरक्षा देता है। वकील का यह भी कहना है कि ब्रूना ग्रीन कार्ड लेने की प्रोसेस में थीं और उन्हें अचानक गिरफ्तार कर लेने से उनका छोटा बच्चा भी उनसे अलग हो गया। ब्रूना के 11 साल के बेटे की परवरिश उसके पिता माइकल लेविट कर रहे हैं, जो कैरोलीन लेविट के भाई हैं। माइकल ने कहा कि उनकी सबसे बड़ी चिंता उनके बेटे की सुरक्षा और उसकी प्राइवैसी है। ट्रम्प प्रशासन ने इस साल से इमिग्रेशन कानूनों को बेहद सख्ती से लागू करना शुरू किया है। सरकार का कहना है कि जो भी लोग अमेरिका में बिना इजाजत के रह रहे हैं, उन्हें देश से निकाला जा सकता है।

1998 में आई थीं अमेरिका, अब हटाए जाने की कार्यवाही जारी : ब्रूना फरेइरा को 1998 में बचपन में ही अमेरिका लाया गया था। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के प्रवक्ता के मुताबिक, उन्होंने

12 माइक्रो-सेटेलाइट्स को कक्षा में स्थापित करना है। लॉन्च के बाद अधिकारी लगातार निगरानी कर रहे हैं कि सभी सैटेलाइट्स सही ऊंचाई पर पहुंचते हैं या नहीं। मुख्य सैटेलाइट की विशेषताएं : इस मिशन में भेजा गया मुख्य सैटेलाइट राष्ट्रीय योजना में यह चौथा लॉन्च है। इस मिशन ने दक्षिण कोरिया की अंतरिक्ष तकनीक में बढ़ती क्षमता को एक बार फिर उजागर किया है। तीन चरणों वाला नूरी रॉकेट दक्षिण-पश्चिमी तट पर स्थित गौहड के अंतरिक्ष केंद्र से सबह उड़ान भरा। एयरोस्पेस अधिकारियों के अनुसार, रॉकेट का उद्देश्य 516 किलोग्राम वजनी विज्ञान सैटेलाइट समेत

बचपन में अमेरिका लाए गए कुछ अपात्र अप्रवासियों को निर्वासन से अस्थायी सुरक्षा और काम करने की अनुमति देती है। यह कार्यक्रम दो साल के लिए वैध होता है और इसे रिन्यू किया जा सकता है। वकील का दावा: ट्रंप प्रशासन की वजह से डीएसीए नवीनीकरण में बाधा उनके वकील पोमेरलो का कहना है कि फरेइरा पहले डीएसीए लाभार्थी थीं, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कार्यक्रम समाप्त करने की कोशिश के कारण उनका नवीनीकरण रुक गया। वकील के अनुसार, फरेइरा फिलहाल अपने लिए अमेरिकी नागरिकता प्राप्त करने की वैध प्रक्रिया में थीं। परिवारिक पृष्ठभूमि: लेविट परिवार से पुराना संबंध : सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, फरेइरा ट्रंप की प्रेस सेक्रेटरी करोलिन लेविट के भाई माइकल लेविट की पूर्व मोतार हैं। दोनों का एक 11 वर्षीय बेटा है, जो वर्तमान में अपने पिता के

अंतरिक्ष में परखने का एक विशेष सिस्टम भी लगाया गया है। 12 छोटे 'क्यूब' सैटेलाइट्स भी भेजे गए : इस मिशन की एक और खास बात यह रही कि विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों द्वारा तैयार 12 छोटे क्यूब सैटेलाइट्स भी रॉकेट में शामिल थीं। इनमें लगाई गई तकनीकों में जीपीएस आधारित पृथ्वी के वायुमंडल का अध्ययन, समुद्री प्लास्टिक पर नजर रखने के लिए इन्फ्रारेड कैमरे, सौर सेल परीक्षण सिस्टम और कम्प्यूटिकेशन डिविजमेंट की परख करने वाली इकाइयां शामिल हैं। पिछले लॉन्च की तुलना में बड़ा कदम : यह प्रक्षेपण नूरी रॉकेट का मई

2023 के बाद पहला लॉन्च है। इससे पहले 2023 में नूरी रॉकेट ने 180 किलोग्राम वजनी अवलोकन सैटेलाइट को सफलतापूर्वक कक्षा में पहुंचाया था। नूरी का पहला लॉन्च अक्टूबर 2021 में किया गया था, जो डबी सैटेलाइट को कक्षा में स्थापित करने में असफल रहा था। इसलिए इस चौथे प्रयास को दक्षिण कोरिया की अंतरिक्ष तकनीक में स्थिरता और सुधार का महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है। इस मिशन की सफलता से दक्षिण कोरिया की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षा को नई ऊर्जा मिली है। नूरी कार्यक्रम के तहत किए जाने वाले अगले दो मिशन 2027 तक पूरे किए जाएंगे, जिनमें और उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा।

वाशिंगटन, एजेंसी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के रोज गार्डन में थैंक्सगिविंग समारोह में टर्की पक्षी को औपचारिक माफी देकर व्हाइट हाउस की पारंपरिक रस्म में सद्भावना के बजाय डेमोक्रेट्स का अपमान किया। उन्होंने टर्की को अल साल्वाडोर की एक बदनाम जेल में भेजने का मजाक उड़या, जिसका इस्तेमाल अमेरिका से निकाले गए शरणार्थियों को रखने के लिए किया जाता है। वह बोले, पक्षियों का नाम डेमोक्रेटिक दिग्गज चक शुमर और नैसी पेलेसी के नाम पर चक और नैसी होना चाहिए। ट्रंप ने कहा, मैं उन्हें (डेमोक्रेट्स को) माफ नहीं करूंगा। ट्रंप ने दावा किया कि तानाबंश राष्ट्रपति जो बाइडन की ओर से टर्की को दी गई माफी अमान्य थी क्योंकि उन्होंने ऑटोपेन का इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा, हंटर (बाइडन) कहा है? इसके साथ ही उन्होंने इशारा दिया कि पूर्व राष्ट्रपति के बेटे को एक बार फिर कानूनी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। बाइडन ने अपने कार्यकाल के अंत में हंटर बाइडन को माफी देने के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। ट्रंप ने यह सब मजाक तब शुरू किया जब उन्होंने इलिनॉइस के गवर्नर और डेमोक्रेट नेता जेबी

प्रिंजकर पर अपना ध्यान केंद्रित किया। वह शिकागो में नेशनल गार्ड टैनाली संबंधी व्हाइट हाउस की योजनाओं का विरोध कर रहे हैं। पत्रकारों के बीच फरेइरा को अपराधिक मामला नहीं है। वे डीएसीए नाम के उस सरकारी प्रोग्राम के

बचपन में अमेरिका लाए गए कुछ अपात्र अप्रवासियों को निर्वासन से अस्थायी सुरक्षा और काम करने की अनुमति देती है। यह कार्यक्रम दो साल के लिए वैध होता है और इसे रिन्यू किया जा सकता है। वकील का दावा: ट्रंप प्रशासन की वजह से डीएसीए नवीनीकरण में बाधा उनके वकील पोमेरलो का कहना है कि फरेइरा पहले डीएसीए लाभार्थी थीं, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कार्यक्रम समाप्त करने की कोशिश के कारण उनका नवीनीकरण रुक गया। वकील के अनुसार, फरेइरा फिलहाल अपने लिए अमेरिकी नागरिकता प्राप्त करने की वैध प्रक्रिया में थीं। परिवारिक पृष्ठभूमि: लेविट परिवार से पुराना संबंध : सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, फरेइरा ट्रंप की प्रेस सेक्रेटरी करोलिन लेविट के भाई माइकल लेविट की पूर्व मोतार हैं। दोनों का एक 11 वर्षीय बेटा है, जो वर्तमान में अपने पिता के

रुका और उसने हेंड्रान निकालर फायरिंग करनेी शुरू कर दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फायरिंग का शिकार दोनों नेशनल गार्ड्स सदस्यों के सिर में गोली लगी है, जिससे उनकी हालत गंभीर है। इस गोलीबारी के बाद आसपास मौजूद अन्य सदस्यों ने तुरंत ही वहां आकर हालात को काबू में किया। एफबीआई प्रमुख काश पटेल ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर जानकारी ली। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आरोपी को हिरासत में लिया गया है। मामले की जांच जारी है। उसका क्या मकसद था इसके बारे में फिलहाल जांच के बाद ही पता चलेगा। अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों संग किया काम : एपी की रिपोर्ट के मुताबिक, इस मामले की जानकारी रखने वाले दो कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने बताया कि रहमानुल्लाह पिछले काफी समय से वाशिंगटन में ही रह रहा है, लेकिन अभी उसकी और जानकारी निकासी जा रही है। एनबीसी ने रहमानुल्लाह के एक करीबी रिश्तेदार के हवाले से बताया कि रहमानुल्लाह और उसकी पत्नी के कुल पांच लड़कें हैं। 2021 में अमेरिका आने से पहले वह अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों के साथ काम करता था। लकनवाल ने 10 साल तक अफगान से काम किया। उस दौरान वह कंधार के एक अड्डे पर तैनात रहा।

जर्मनी बोला- रूस जंग खत्म करने को तैयार नहीं देश का रक्षा बजट बढ़ाने का ऐलान ; 2029 तक नाटो पर हमला कर सकते हैं पुतिन बर्लिन, एजेंसी। जर्मनी ने रूस पर आरोप लगाया है कि वह यूक्रेन जंग खत्म करने के लिए किसी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं दिख रहा है। बुधवार को जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने संसद में कहा कि रूस ने यूक्रेन के लिए तैयार की गई नई शांति योजना पर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी है। उन्होंने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बयानों में शांति की कोई इच्छा नहीं दिखती। बोरिस ने कहा, पुतिन की प्रतिक्रिया से साफ है कि वह किसी तरह का समझौता नहीं करना चाहते। बोरिस ने बताया कि इसी वजह से जर्मनी अपने रक्षा बजट में बढ़ोतरी करेगा। साथ ही यूक्रेन को सैन्य मदद भी बढ़ाएगा। 2029 तक नाटो पर हमला कर सकता है रूस : जर्मनी के विदेश मंत्री योहान वेडफुल ने मंगलवार चेतावनी दी है कि रूस अगले चार साल में किसी ह्ज्जह देश

बर्लिन, एजेंसी। जर्मनी ने रूस पर आरोप लगाया है कि वह यूक्रेन जंग खत्म करने के लिए किसी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं दिख रहा है। बुधवार को जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने संसद में कहा कि रूस ने यूक्रेन के लिए तैयार की गई नई शांति योजना पर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी है। उन्होंने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बयानों में शांति की कोई इच्छा नहीं दिखती। बोरिस ने कहा, पुतिन की प्रतिक्रिया से साफ है कि वह किसी तरह का समझौता नहीं करना चाहते। बोरिस ने बताया कि इसी वजह से जर्मनी अपने रक्षा बजट में बढ़ोतरी करेगा। साथ ही यूक्रेन को सैन्य मदद भी बढ़ाएगा। 2029 तक नाटो पर हमला कर सकता है रूस : जर्मनी के विदेश मंत्री योहान वेडफुल ने मंगलवार चेतावनी दी है कि रूस अगले चार साल में किसी ह्ज्जह देश

बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि रूस ने अपनी अर्थव्यवस्था और समाज को काफी हद तक युद्ध के हिसाब से ढाल दिया है। साथ ही, रूस जरूरत से ज्यादा सैनिकों को भर्ती कर रहा है। लगभग हर महीने एक नई डिंविजन तैयार की जा रही है। नाटो चीफ बोले- रूस शांति समझौते के बाद भी खतरा : नाटो महासचिव मार्क रूटे ने कहा है

बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि रूस ने अपनी अर्थव्यवस्था और समाज को काफी हद तक युद्ध के हिसाब से ढाल दिया है। साथ ही, रूस जरूरत से ज्यादा सैनिकों को भर्ती कर रहा है। लगभग हर महीने एक नई डिंविजन तैयार की जा रही है। नाटो चीफ बोले- रूस शांति समझौते के बाद भी खतरा : नाटो महासचिव मार्क रूटे ने कहा है

बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि रूस ने अपनी अर्थव्यवस्था और समाज को काफी हद तक युद्ध के हिसाब से ढाल दिया है। साथ ही, रूस जरूरत से ज्यादा सैनिकों को भर्ती कर रहा है। लगभग हर महीने एक नई डिंविजन तैयार की जा रही है। नाटो चीफ बोले- रूस शांति समझौते के बाद भी खतरा : नाटो महासचिव मार्क रूटे ने कहा है

बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि रूस ने अपनी अर्थव्यवस्था और समाज को काफी हद तक युद्ध के हिसाब से ढाल दिया है। साथ ही, रूस जरूरत से ज्यादा सैनिकों को भर्ती कर रहा है। लगभग हर महीने एक नई डिंविजन तैयार की जा रही है। नाटो चीफ बोले- रूस शांति समझौते के बाद भी खतरा : नाटो महासचिव मार्क रूटे ने कहा है

बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि रूस ने अपनी अर्थव्यवस्था और समाज को काफी हद तक युद्ध के हिसाब से ढाल दिया है। साथ ही, रूस जरूरत से ज्यादा सैनिकों को भर्ती कर रहा है। लगभग हर महीने एक नई डिंविजन तैयार की जा रही है। नाटो चीफ बोले- रूस शांति समझौते के बाद भी खतरा : नाटो महासचिव मार्क रूटे ने कहा है

बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि रूस ने अपनी अर्थव्यवस्था और समाज को काफी हद तक युद्ध के हिसाब से ढाल दिया है। साथ ही, रूस जरूरत से ज्यादा सैनिकों को भर्ती कर रहा है। लगभग हर महीने एक नई डिंविजन तैयार की जा रही है। नाटो चीफ बोले- रूस शांति समझौते के बाद भी खतरा : नाटो महासचिव मार्क रूटे ने कहा है

बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि रूस ने अपनी अर्थव्यवस्था और समाज को काफी हद तक युद्ध के हिसाब से ढाल दिया है। साथ ही, रूस जरूरत से ज्यादा सैनिकों को भर्ती कर रहा है। लगभग हर महीने एक नई डिंविजन तैयार की जा रही है। नाटो चीफ बोले- रूस शांति समझौते के बाद भी खतरा : नाटो महासचिव मार्क रूटे ने कहा है

बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि रूस ने अपनी अर्थव्यवस्था और समाज को काफी हद तक युद्ध के हिसाब से ढाल दिया है। साथ ही, रूस जरूरत से ज्यादा सैनिकों को भर्ती कर रहा है। लगभग हर महीने एक नई डिंविजन तैयार की जा रही है। नाटो चीफ बोले- रूस शांति समझौते के बाद भी खतरा : नाटो महासचिव मार्क रूटे ने कहा है

बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि रूस ने अपनी अर्थव्यवस्था और समाज को काफी हद तक युद्ध के हिसाब से ढाल दिया है। साथ ही, रूस जरूरत से ज्यादा सैनिकों को भर्ती कर रहा है। लगभग हर महीने एक नई डिंविजन तैयार की जा रही है। नाटो चीफ बोले- रूस शांति समझौते के बाद भी खतरा : नाटो महासचिव मार्क रूटे ने कहा है

बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि रूस ने अपनी अर्थव्यवस्था और समाज को काफी हद तक युद्ध के हिसाब से ढाल दिया है। साथ ही, रूस जरूरत से ज्यादा सैनिकों को भर्ती कर रहा है। लगभग हर महीने एक नई डिंविजन तैयार की जा रही है। नाटो चीफ बोले- रूस शांति समझौते के बाद भी खतरा : नाटो महासचिव मार्क रूटे ने कहा है

बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि रूस ने अपनी अर्थव्यवस्था और समाज को काफी हद तक युद्ध के हिसाब से ढाल दिया है। साथ ही, रूस जरूरत से ज्यादा सैनिकों को भर्ती कर रहा है। लगभग हर महीने एक नई डिंविजन तैयार की जा रही है। नाटो चीफ बोले- रूस शांति समझौते के बाद भी खतरा : नाटो महासचिव मार्क रूटे ने कहा है

बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि रूस ने अपनी अर्थव्यवस्था और समाज को काफी हद तक युद्ध के हिसाब से ढाल दिया है। साथ ही, रूस जरूरत से ज्यादा सैनिकों को भर्ती कर रहा है। लगभग हर महीने एक नई डिंविजन तैयार की जा रही है। नाटो चीफ बोले- रूस शांति समझौते के बाद भी खतरा : नाटो महासचिव मार्क रूटे ने कहा है

बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि रूस ने अपनी अर्थव्यवस्था और समाज को काफी हद तक युद्ध के हिसाब से ढाल दिया है। साथ ही, रूस जरूरत से ज्यादा सैनिकों को भर्ती कर रहा है। लगभग हर महीने एक नई डिंविजन तैयार की जा रही है। नाटो चीफ बोले- रूस शांति समझौते के बाद भी खतरा : नाटो महासचिव मार्क रूटे ने कहा है

बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि रूस ने अपनी अर्थव्यवस्था और समाज को काफी हद तक युद्ध के हिसाब से ढाल दिया है। साथ ही, रूस जरूरत से ज्यादा सैनिकों को भर्ती कर रहा है। लगभग हर महीने एक नई डिंविजन तैयार की जा रही है। नाटो चीफ बोले- रूस शांति समझौते के बाद भी खतरा : नाटो महासचिव मार्क रूटे ने कहा है

बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि रूस ने अपनी अर्थव्यवस्था और समाज को काफी हद तक युद्ध के हिसाब से ढाल दिया है। साथ ही, रूस जरूरत से ज्यादा सैनिकों को भर्ती कर रहा है। लगभग हर महीने एक नई डिंविजन तैयार की जा रही है। नाटो चीफ बोले- रूस शांति समझौते के बाद भी खतरा : नाटो महासचिव मार्क रूटे ने कहा है

बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि रूस ने अपनी अर्थव्यवस्था और समाज को काफी हद तक युद्ध के हिसाब से ढाल दिया है। साथ ही, रूस जरूरत से ज्यादा सैनिकों को भर्ती कर रहा है। लगभग हर महीने एक नई डिंविजन तैयार की जा रही है। नाटो चीफ बोले- रूस शांति समझौते के बाद भी खतरा : नाटो महासचिव मार्क रूटे ने कहा है

बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि रूस ने अपनी अर्थव्यवस्था और समाज को काफी हद तक युद्ध के हिसाब से ढाल दिया है। साथ ही, रूस जरूरत से ज्यादा सैनिकों को भर्ती कर रहा है। लगभग हर महीने एक नई डिंविजन तैयार की जा रही है। नाटो चीफ बोले- रूस शांति समझौते के बाद भी खतरा : नाटो महासचिव मार्क रूटे ने कहा है

बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि रूस ने अपनी अर्थव्यवस्था और समाज को काफी हद तक युद्ध के हिसाब से ढाल दिया है। साथ ही, रूस जरूरत से ज्यादा सैनिकों को भर्ती कर रहा है। लगभग हर महीने एक नई डिंविजन तैयार की जा रही है। नाटो चीफ बोले- रूस शांति समझौते के बाद भी खतरा : नाटो महासचिव मार्क रूटे ने कहा है

बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि रूस ने अपनी अर्थव्यवस्था और समाज को काफी हद तक युद्ध के हिसाब से ढाल दिया है। साथ ही, रूस जरूरत से ज्यादा सैनिकों को भर्ती कर रहा है। लगभग हर महीने एक नई डिंविजन तैयार की जा रही है। नाटो चीफ बोले- रूस शांति समझौते के बाद भी खतरा : नाटो महासचिव मार्क रूटे ने कहा है

बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि रूस ने अपनी अर्थव्यवस्था और समाज को काफी हद तक युद्ध के हिसाब से ढाल दिया है। साथ ही, रूस जरूरत से ज्यादा सैनिकों को भर्ती कर रहा है। लगभग हर महीने एक नई डिंविजन तैयार की जा रही है। नाटो चीफ बोले- रूस शांति समझौते के बाद भी खतरा : नाटो महासचिव मार्क रूटे ने कहा है

बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि रूस ने अपनी अर्थव्यवस्था और समाज को काफी हद तक युद्ध के हिसाब से ढाल दिया है। साथ ही, रूस जरूरत से ज्यादा सैनिकों को भर्ती कर रहा है। लगभग हर महीने एक नई डिंविजन तैयार की जा रही है। नाटो चीफ बोले- रूस शांति समझौते के बाद भी खतरा : नाटो महासचिव मार्क रूटे ने कहा है

बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि रूस ने अपनी अर्थव्यवस्था और समाज को काफी हद तक युद्ध के हिसाब से ढाल दिया है। साथ ही, रूस जरूरत से ज्यादा सैनिकों को भर्ती कर रहा है। लगभग हर महीने एक नई डिंविजन तैयार की जा रही है। नाटो चीफ बोले- रूस शांति समझौते के बाद भी खतरा : नाटो महासचिव मार्क रूटे ने कहा है

बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि रूस ने अपनी अर्थव्यवस्था और समाज को काफी हद तक युद्ध के हिसाब से ढाल दिया है। साथ ही, रूस जरूरत से ज्यादा सैनिकों को भर्ती कर रहा है। लगभग हर महीने एक नई डिंविजन तैयार की जा रही है। नाटो चीफ बोले- रूस शांति समझौते के बाद भी खतरा : नाटो महासचिव मार्क रूटे ने कहा है

बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि रूस ने अपनी अर्थव्यवस्था और समाज को काफी हद तक युद्ध के हिसाब से ढाल दिया है। साथ ही, रूस जरूरत से ज्यादा सैनिकों को भर्ती कर रहा है। लगभग हर महीने एक नई डिंविजन तैयार की जा रही है। नाटो चीफ बोले- रूस शांति समझौते के बाद भी खतरा : नाटो महासचिव मार्क रूटे ने कहा है

बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि रूस ने अपनी अर्थव्यवस्था और समाज को काफी हद तक युद्ध के हिसाब से ढाल दिया है। साथ ही, रूस जरूरत से ज्यादा सैनिकों को भर्ती कर रहा है। लगभग हर महीने एक नई डिंविजन तैयार की जा रही है। नाटो चीफ बोले- रूस शांति समझौते के बाद भी खतरा : नाटो महासचिव मार्क रूटे ने कहा है

बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि रूस ने अपनी अर्थव्यवस्था और समाज को काफी हद तक युद्ध के हिसाब से ढाल दिया है। साथ ही, रूस जरूरत से ज्यादा सैनिकों को भर्ती कर रहा है। लगभग हर महीने एक नई डिंविजन तैयार की जा रही है। नाटो चीफ बोले- रूस शांति समझौते के बाद भी खतरा : नाटो महासचिव मार्क रूटे ने कहा है

बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि रूस ने अपनी अर्थव्यवस्था और समाज को काफी हद तक युद्ध के हिसाब से ढाल दिया है। साथ ही, रूस जरूरत से ज्यादा सैनिकों को भर्ती कर रहा है। लगभग हर महीने एक नई डिंविजन तैयार की जा रही है। नाटो चीफ बोले- रूस शांति समझौते के बाद भी खतरा : नाटो महासचिव मार्क रूटे ने कहा है

बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि रूस ने अपनी अर्थव्यवस्था और समाज को काफी हद तक युद्ध के हिसाब से ढाल दिया है। साथ ही, रूस जरूरत से ज्यादा सैनिकों को भर्ती कर रहा है। लगभग हर महीने एक नई डिंविजन तैयार की जा रही है। नाटो चीफ बोले- रूस शांति समझौते के बाद भी खतरा : नाटो महासचिव मार्क रूटे ने कहा है

बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि रूस ने अपनी अर्थव्यवस्था और समाज को काफी हद तक युद्ध के हिसाब से ढाल दिया है। साथ ही, रूस जरूरत से ज्यादा सैनिकों को भर्ती कर रहा है। लगभग हर महीने एक नई डिंविजन तैयार की जा रही है। नाटो चीफ बोले- रूस शांति समझौते के बाद भी खतरा : नाटो महासचिव मार्क रूटे ने कहा है

बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि रूस ने अपनी अर्थव्यवस्था और समाज को काफी हद तक युद्ध के हिसाब से ढाल दिया है। साथ ही, रूस जरूरत से ज्यादा सैनिकों को भर्ती कर रहा है। लगभग हर महीने एक नई डिंविजन तैयार की जा रही है। नाटो चीफ बोले- रूस शांति समझौते के बाद भी खतरा : नाटो महासचिव मार्क रूटे ने कहा है

बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि रूस ने अपनी अर्थव्यवस्था और समाज को काफी हद तक युद्ध के हिसाब से ढाल दिया है। साथ ही, रूस जरूरत से ज्यादा सैनिकों को भर्ती कर रहा है। लगभग हर महीने एक नई डिंविजन तैयार की जा रही है। नाटो चीफ बोले- रूस शांति समझौते के बाद भी खतरा : नाटो महासचिव मार्क रूटे ने कहा है

बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि रूस ने अपनी अर्थव्यवस्था और समाज को काफी हद तक युद्ध के हिसाब से ढाल दिया है। साथ ही, रूस जरूरत से ज्यादा सैनिकों को भर्ती कर रहा है। लगभग हर महीने एक नई डिंविजन तैयार की जा रही है। नाटो चीफ बोले- रूस शांति समझौते के बाद भी खतरा : नाटो महासचिव मार्क रूटे ने कहा है

बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि रूस ने अपनी अर्थव्यवस्था और समाज को काफी हद तक युद्ध के हिसाब से ढाल दिया है। साथ ही, रूस जरूरत से ज्यादा सैनिकों को भर्ती कर रहा है। लगभग हर महीने एक नई डिंविजन तैयार की जा रही है। नाटो चीफ बोले- रूस शांति समझौते के बाद भी खतरा : नाटो महासचिव मार्क रूटे ने कहा है

बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि रूस ने अपनी अर्थव्यवस्था और समाज को काफी हद तक युद्ध के हिसाब से ढाल दिया है। साथ ही, रूस जरूरत से ज्यादा सैनिकों को भर्ती कर रहा है। लगभग हर महीने एक नई डिंविजन तैयार की जा रही है। नाटो चीफ बोले- रूस शांति समझौते के बाद भी खतरा : नाटो महासचिव मार्क रूटे ने कहा है

बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि रूस ने अपनी अर्थव्यवस्था और समाज को काफी हद तक युद्ध के हिसाब से ढाल दिया है। साथ ही, रूस जरूरत से ज्यादा सैनिकों को भर्ती कर रहा है। लगभग हर महीने एक नई डिंविजन तैयार की जा रही है। नाटो चीफ बोले- रूस शांति समझौते के बाद भी खतरा : नाटो महासचिव मार्क रूटे ने कहा है

बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि रूस ने अपनी अर्थव्यवस्था और समाज को काफी हद तक युद्ध के हिसाब से ढाल दिया है। साथ ही, रूस जरूरत से ज्यादा सैनिकों को भर्ती कर रहा है। लगभग हर महीने एक नई डिंविजन तैयार की जा रही है। नाटो चीफ बोले- रूस शांति समझौते के बाद भी खतरा : नाटो महासचिव मार्क रूटे ने कहा है

बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि रूस ने अपनी अर्थव्यवस्था और समाज को काफी हद तक युद्ध के हिसाब से ढाल दिया है। साथ ही, रूस जरूरत से ज्यादा सैनिकों को भर्ती कर रहा है। लगभग हर महीने एक नई डिंविजन तैयार की जा रही है। नाटो चीफ बोले- रूस शांति समझौते के बाद भी खतरा : नाटो महासचिव मार्क रूटे ने कहा है

बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि रूस ने अपनी अर्थव्यवस्था और समाज को काफी